(ग) कार्यरत पोतों की संख्या कितनी है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा ढोए गए माल की प्रमात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उसी अवधि के दौरान उसे वर्षवार कितना-कितना घाटा हुआ; और

(ङ) क्या सरकार निगम को हो रहे निरन्तर घाटे को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था से आमूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री **(श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, हां ।

(ख) 158 जहाज

(ग) 134 जहाज

(करोड़ रु०)

(घ) वर्ष	ढाया गया कार्गो (टन)	सामग्री के परिवहन में प्रचालन घाटा
1988–89	3,04,356	4.90
1989–90	4,10,331	4.37
1990–91	3,35,412	6.23 (अनंतिम)

(ङ) पुराने तथा गैर मरम्मत योग्य जहाजों की स्क्रैपिंग करके जहाज-बेड़े का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । कार्गो क्षमता जो कि 1985–86 में 4.15 लाख टन थी, 1990–91 में बढ़ कर 5.2 लाख टन हो गई है । पहले ही आर्डर दिए जा चुके शेष जहाजों की डिलीवरी के पश्चात् यह बढ़ कर लगभग 10 लाख टन हो जाएगी ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के जहाजों को बंगला देश से होकर कलकत्ता से उत्तर-पूर्व जाने की अनुमति देने के लिए बंगला देश के साथ 4–10–91 से 2 वर्ष की और अवधि के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है ।

गैर-सरकारी द्वारा चलायी जाने के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हो रहे घाटे

*53. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1991 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "डी०टी०सी० इन्कर्स मेजर लासिज आन किलोमीटर स्कीम सी०ए०जी० रिपोर्ट" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्कीम के अधीन गैर-सरकारी बसों के चलाए जाने से संबंधित अपनी नीति की समीक्षा की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जुलाई, 1989 में सरकार ने ऐसी एक वैकल्पिक स्कीम जिसके अधीन और गैर-सरकारी स्वामित्व की बस लाभ में चलायी जा सके, की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ङ) यदि नहीं तो इस प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ; और

(च) क्या समिति गठित करते समय उससे एक निश्चित अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध नहीं किया गया था, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस समिति पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान "बसाओ और रखो" (अर्न एंड कीप) प्रणाली को कुछेक तथाकथित सीमाएं होने और दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को वैकल्पिक सुझाव देने के प्रयोजन से विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने जुलाई, 1989 में एक दल का गठन किया था। और इस दल ने कोई रिपोर्ट नहीं दी।

(ख) और (ड़) जी, नहीं। अब यह दल विद्यमान नहीं है।

(च) रिपोर्ट पेश करने के लिए समिति में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। इस समिति पर सरकार ने कुछ व्यय नहीं किया।

उड़ानों का बन्द किया जाना

*54. श्री अजीत जोगी :

कुमारी आदिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया, वायुदूत और पवनहंस लिमिटेड को हाल में बन्द की गई उड़ानों की संख्या कितनी है ;

(ख) ये उड़ान कब से बन्द की गई हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस कदम से प्रभावित हुए वायुमार्ग विमान सेवाओं की संख्या कितनी है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारी कदम उठाए हैं या उठाने का

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान एयर इंडिया, वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड ने कोई उड़ान बन्द नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Hardship due to increase in visa and Consular fees

*55. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the steep increase in visa and consular fees levied by our consulates;

(b) what are the reasons behind such increase;

(c) what has been the total visa and consular fees collected by all our missions in 1989-90 and 1990-91, separately; and

(d) what steps are being taken to review the steep increase and reduce the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALERIO): (a) Visa fees has been increased w.e.f. 1.11.91. Consular fee has, so far, not been increased.

(b) The visa fees have been increased due to the following reasons:

(i) In 1990 the visa regime was liberalised and the duration of visa was extended upto 5 years but the visa fees was not appropriately increased.

(ii) Tre recent devaluation of Indian rupee made it imperative to revise the visa fee upwards.

(iii) Indian visa fee was reduced unilaterally in favour of nationals of UK, USA, FRG, France, Spain, Italy and Netherlands for one year. But these countries did not reciprocate to our action.